भारत के निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादों की स्थिति आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में अध्ययन

*डॉ. शीलचन्द्र गुप्ता

शोधपत्र-अर्थशास्त्र

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने देश के आर्थिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अत्यधिक महत्व देते हुए उसे विकास का इंजन निरूपित किया था।[1] भारत में स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद अपनाये गये आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ से ही विदेशी विनिमय संबंधी कठिनाईया सामने आयी है। सरकार ने निर्यात संवर्द्धन की आवश्यकता को स्वीकार करके आयात–निर्यात नीति, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों के द्वारा निर्यातों में वृद्धि करने के विशेष प्रयास किये है। भारत जैसे अल्पविकसित देश अधिकतर निर्यातों के लिए कुछ कृषि पदार्थो क उत्पादन में विशिष्टिकरण करते है। जब निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते है तो उनके निर्यातों में वृद्धि होती है जिससे वे अधिक विदेशी विनिमय कमाते है। जब अर्थव्यवस्था खाद्य–उत्पादनमें आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो खाद्यान्नों के बढ़े हुए विक्रय अतिरेक से विदेशी विनिमय में बचत होती है। खाद्य तथा निर्यात योग्य फसलों के अधिक उत्पादन से न केवल विदेशी विनिमय की बचत तथा कमाई होती है बल्कि अर्थव्यवस्थाके अन्य क्षेत्रो का विकास भी होता है।[2]

प्राचीन काल से ही भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहॉ की अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही जीविकोपार्जन करती है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के लिए कृषि अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति करती है। कृषि सभी उद्योंगो की जननी और मानव जीवन की पोषक रही है। इसे आर्थिक विकास की कुंजी भी कहा जाता है क्योंकि औद्योगिकरण मूल रूप से कृषिगत विकास की ही देन है। विशेष रूप से भारत जैसे देश जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है अपने सीमित साधनों द्वारा आर्थिक विकास की ऊँची दर तब तक प्राप्त नही कर सकते जब तक कि वे अपने आधारभूत कृषि उद्योग को उन्नत न कर ले। प्रो. लुईस, कोले, हूवर वाइनर तथा किन्डल बर्जर जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि विकास प्रक्रिया में कृषि विकास को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिये क्योंकि घरेलु मांग की आपूर्ति, आत्मनिर्भरता एवं निर्यात वृद्धि जैसी आधारभूत समस्याएँ कृषिगत विकास से ही हल की जा सकती है। कृषि का विकास एवं विस्तार होने से देश की निर्यात क्षमता बढ़ जाती है जिसका प्रभाव अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित करना होता है।[3]

भारत जैसे विकासशील देश खाद्य–पदार्थो और कच्चे माल के निर्यातक रहे है। जैसे–जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, कच्चे माल का निर्यात कम हो जाता है क्योकि देश में बढते हुए उद्योगों के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण निर्यात के लिए उपलब्ध खाद्य अतिरेक या तो बहुत कम हो जाता है या घाटे में परिवर्तित हो जाता है। परिणामस्वरूप विकासशील अर्थव्यवस्था को अपने निर्यात बढाने के लिए नई वस्तुओं और नये बाजार ढूंढने पड़ते है।[4] भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। किन्तु कृषि निर्यातों को ओर उदार बनाने के सम्बंध में **विमल जालान** का तर्क है कि इस दिशा में बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है क्योकि भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्से की दृष्टि से तथा रोजगार, गरीबी और उपभोक्ता कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए खाद्यान्नों में निर्यातों को अकस्मात खोल देने से घरेलु कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है जिसका गरीब जनता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोपिय संघ के देशों द्वारा अपने कृषि निर्यातों को जो व्यापक सहायता दी जाती है उससे भारत के लिए स्थिति स्थिति और जटिल हो जाती है। उपर्युक्त कारणो से विमल जालान का तर्क है कि ''व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया पहले उन गैर–खाद्य वस्तुओं में प्रारम्भ करना चाहिये जिनका निर्धन लोगो के उपभोग में महत्वपूर्ण स्थान नही है।''[5] भारत में वर्ष 1991 से अपनाये गये व्यापार सुधारो का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के निर्यातों को

* सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ (म.प्र.)

विशेष प्रोत्साहन दिया गया है । आयात निर्यात नीति 2002–07 में भारत सरकार ने कृषि निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की । इसमें ताजे व परिष्कृत, फल फूल, सब्जियॉ, पोल्ट्री व डेयरी उत्पाद तथा गेहूँ व चावल उत्पादों के लिए परिवहन सहायता की व्यवस्था की गई । इससे किसान कृषि विविधीकरण के लिए प्रेरित होगें । भारतीय खाद्य निगम के पास जमा खाद्यान्नों के भण्डारों को निर्यात करने के लिए भी परिवहन सहायता की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त कृषि निर्यात क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है जिससे क्षेत्र विशेष में उपलब्ध बागवानी उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सके ।[6] नयी विदेशी व्यापार नीति 2004–09 में कृषि क्षेत्र के लिये फलों, सब्जियॉ, फूलों, तुच्छ वन उत्पादों, दुग्ध, मुर्गीपालन तथा उनके मूल्य वृद्धि उत्पादों के लिये व एक नयी विशेष कृषि उपज योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना का उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्यातकों का प्रोत्साहन देकर फलों, सब्जियों , फूलों , साधारण वन्य उपज, डेयरी, पौल्ट्री, मांस ओर इनके मूल्य संबंधित उत्पादों को बढावा देना है ।[7]

उद्देश्य एवं अध्ययन प्रविधि भारत में आर्थिक उदारीकरण और व्यापार सुधारों की नीति (1991) को अपनाये हुए डेढ दशक से अधिक समय हो गया है । प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारत में व्यापार सुधार एवं निर्यात संवर्द्धन नीति का कृषि उत्पादों के निर्यातों पर प्रभाव का अध्ययन करना है । इसके अन्तर्गत कृषि निर्यातों की संरचना एवं उसमें हुये महत्वपूर्ण परिवर्तनों का गहन विश्लेषण किया गया है । उसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिये आर्थिक उदारीकरण के पूर्व एवं उदारीकरण के बाद भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है । इस शोध–पत्र की अध्ययन प्रविधि द्वितीयक समंको के विश्लेषण पर आधारित है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा सन् 1942 में 2.2 प्रतिशत था जो लगातार कम होकर 1983 में 0.5 प्रतिशत रह गया जिससे देश के समक्ष विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात वर्ष 1991 में अपनाये गये आर्थिक सुधारों के बाद विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा बढकर वर्ष 2001 में 0.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2008 में 1.1 प्रतिशत हो गया है ।[8] भारत के विदेशी व्यापार का एक बढा भाग कृषि से प्राप्त होता है । विगत कुछ वर्षो में भारत के निर्यात एवं कृषि वस्तुओं के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य में बडोत्तरी हुई है । कृषि क्षेत्र से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चाय, कॉफी, तम्बाकु, काजु, जूट, कपास, ऊन, बादान, खाद्य तेल, सुपारी, गोंद, किसमिस, चमडा, खली, मसाले, चावल, एवं फल प्रमुख है । कृषि वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय एवं उसका देश के कुल निर्यात में योगदान सारणी–1 में दर्शाया गया हैं ।

कृषि उत्पादों के निर्यात की संरचना भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात व्यापार की संरचना में नियोजनकाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये है । आर्थिक सुधारों के पूर्व (1981से 1991) कृषि निर्यात में जहॉ खली, काजु गिरी, मसाले, चीनी ओर शीरा, कपास एवं मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हुई, वहीं काफी, चाय और मेट, तम्बाकू एवं चावल की निर्यात मात्रा में कमी परिलक्षित हुई । आर्थिक सुधारों के बाद (1991 से 2008) की अवधि मे काफी , खली, तम्बाकु , काजू गिरी, मसाले , चीनी ओर शीरा ,कपास एवं चावल की निर्यात मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । किन्तु चाय और मेट की निर्यात मात्रा में कमी आयी है कृषि वस्तुओं की निर्यात मात्रा एवं उसमें हुए परिवर्तन का ब्यौरा सारणी–2 में दिया गया है।

सारणी–1 भारत में कृषि वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय

वर्ष	कृषि वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय (करोड रू.)	कुल निर्यात आय में कृषि निर्यात का प्रतिशत
1960–61	284	44.2
1980–81	2057	30.6
1990–91	6317	19.4
2000–01	28535	14.0
2007–08	76006	11.6

स्त्रोतः–आर्थिक समीक्षा 2008–09, सारणी–7.3 (क), (ख) पृष्ठ A 86 से 89 सारणी–1 से स्पष्ट है कि जहॉ वर्ष 1960–61 में कृषि वस्तुओं के निर्यात से कुल 284 करोड रूपयें प्राप्त हुये थे जो बढकर 1990–91 में 6317 करोड रूपये तथा 2007–08 में 76006 करोड रूपये हो गये । किन्तु कुल निर्यात व्यापार में कृषि निर्यात का प्रतिशत निरन्तर कम हो रहा है । जहॉ यह प्रतिशत 1960–61 में 44.2 था , घटकर 1990–91 में 19.4 तथा 2007–08 में 11.6 प्रतिशत रह गया ।

सारणी–2 के विश्लेषण से स्पष्ट है वर्ष 1980–81 से 2007–08 की अवधि में भारत में कृषि निर्यात की मात्रा में सबसे अधिक वृद्धि चीनी ओर शीरा के निर्यात में (5654.3 प्रतिशत) हुई है । इसके बाद कपास की निर्यात मात्रा मे 1083.6 प्रतिशत, चावल में 790.1 प्रतिशत, खली में 679.8 प्रतिशत, मसाले में 627.4 प्रतिशत, काजू गिरी में 290.1 प्रतिशत, काफी में 104.2 प्रतिशत तथा तम्बाकू में केवल 89.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । किन्तु चाय और मेट की निर्यात मात्रा में इस अवधि में लगभग 14 प्रतिशत की कमी आयी है ।

मुख्य निर्यातों में कृषि उत्पादों की स्थिति

भारत के निर्यात व्यापार में विगत दो दशकों में कृषि उत्पादों का हिस्सा निरन्तर कम हुआ है । जबकि अयस्क और खनिज विनिर्मित वस्तुए, कच्चा तेल एवं पेट्रालियम उत्पाद, अन्य और अवर्गीकृत मदों की वस्तुओं का हिस्सा बढा है । मुख्य निर्यातों में कृषि और संबंधित वस्तुओं का भाग सारणी–3 में दर्शाया गया है।

सारणी–2 भारत में कृषि निर्यात की मात्रा (हजार टन)

वस्तुएं	1980–81	1990–91	2007–08	1981 से 2008 में परिवर्तन (प्रतिशत)
1. काफी	87.3	86.5	178.3	104.2
2. चाय ओर मेट	229.2	199.1	197.4	(–) 13.9
3. खली	886.0	2447.8	9609.0	679.8
4. तम्बाकू	91.3	87.1	173.3	89.8
5. काजू गिरी	32.3	55.5	126.0	290.1
6. मसाले	84.2	103.3	612.5	627.4
7. चीनी ओर शिरा	97.0	191.0	5582.0	5654.3
8. कपास	131.6	374.4	1557.6	1083.6
9. चावल	726.7	505.0	6468.1	790.1
10. मछली तथा मछली से बनी वस्तुएँ	69.4	158.9	–	–

स्त्रोतः–आर्थिक समीक्षा 2008–09, पृष्ट A– 86 से 88 तक

सारणी–3 मुख्य निर्यातों में कृषि का हिस्सा (प्रतिशत)

वस्तु समूह	1995–96	2000–01	2007–08
I. कृषि ओर संबंधित वस्तुएं	**19.2**	**13.5**	**11.6**
जिसमें से			
1. चाय	1.1	1.0	0.3
2. काफी	1.4	0.6	0.3
3 अनाज	4.7	1.7	0.5
4. अनिर्मित तम्बाकू	0.4	0.3	0.2
5. मसाले	0.7	0.8	0.6
6. काजू	1.2	0.9	0.3
7. आयल मील्स	2.2	1.0	1.2
8. फल सब्जियां और दाले	0.7	0.6	0.5
9. सामुद्रिक उत्पाद	3.2	3.1	1.1
10. कपास	0.2	0.1	1.4
II. अयस्क और खनिज	**3.7**	**2.6**	**5.0**
III विनिर्मित वस्तुएँ	**75.2**	**78.0**	**64.4**
IV. कच्चा तेल एवं पैट्रोलियम उत्पाद	**1.4**	**4.2**	**17.8**
V. अन्य और अवर्गीकृत मदें	**0.5**	**1.7**	**1.2**
कुल योग	100.0	100.0	100.0

स्त्रोतः– आर्थिक समीक्षा 1997–98 पृष्ठ 5–89, आर्थिक समीक्षा 2002–03 पृष्ठ 3 से S- 87 एवं आर्थिक समीक्षा 2008–09 सारणी 7.3 (ख) पृष्ठ A–89 से संकलित ।

सारणी –3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत के मुख्य निर्यातों में एक ओर कृषि जहाँ कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का हिस्सा घटा है, वही दूसरी और कृषि निर्यात की प्रमुख वस्तुओं की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ है । देश के मुख्य निर्यातों में वर्ष 1995–96 से 2007–08 की अवधि में कृषि वस्तुओं, यथा– चाय, काफी , अनाज, अनिर्मित तम्बाकु , मसाले काजू, आयल मील्स, फल सब्जियॉ और दालें, सामुद्रिक उत्पाद का हिस्सा कम हुआ है । केवल कपास का हिस्सा इस अवधि ा में बढा है । कृषि निर्यातों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी है कि उदारीकरण के पूर्व वर्ष 1980–81 में कृषि निर्यात मूल्य में प्रमुख योगदान की वस्तुएं – चाय, और मेट (20.7 प्रतिशत), चावल (10.9 प्रतिशत) मछली और मछली से बनी वस्तुएं (10. 5 प्रतिशत), काफी (10.4 प्रतिशत), तथा कपास (8.0 प्रतिशत) थी । किन्तु उदारीकरण के प्रारंभ (1990–91) में कृषि निर्यात मूल्य में प्रमुख योगदान चाय ओर मेट (16.9 प्रतिशत), मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं (15.2 प्रतिशत), कपास (13.4 प्रतिशत), खली (9.6 प्रतिशत) तथा चावल (7.3 प्रतिशत) का हो गया था । व्यापार उदारीकरण के बाद वर्ष 2007–08 में कृषि निर्यात मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा क्रमशः मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं (9.1 प्रतिशत), चावल (15.5 प्रतिशत), कपास (11. 7 प्रतिशत), खली (10.7 प्रतिशत), चीनी और शीरा (7.4 प्रतिशत), मसाले (5.5 प्रतिशत) एवं फल सब्जियां और दालें (5. 3 प्रतिशत) का हो गया है ।

विश्व कृषि निर्यातों में भारत की भागीदारी भारत में नियोजित आर्थिक विकास एवं नयी कृषि विकास रणनीति (हरित क्रांति) के फलस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुई है । किन्तु विश्वव्यापी कृषि निर्यातों में भारत का हिस्सा निरन्तर घटा है । इसके लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण देश में जनसंख्या की त्रीव गति से वृद्धि होना है । बढती हुई जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के उपरान्त कृषि उत्पादों का निर्यात योग्य अतिरेक कम ही बचता है । विश्व कृषि निर्यातों में भारत का हिस्सा सारणी–4 में दर्शाया गया है ।

सारणी–4 विश्व व्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

वस्तुएं	1980	1990	2006
1. चाय और मेट	27.7	22.1	9.1
2. मसाले	14.5	7.7	13.1
3. तम्बाकु और तम्बाकु उत्पाद	4.4	0.8	1.0
4. कॉफी,चाय, कोको मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	4.0	4.0	2.7
5. चावल	3.7	6.4	14.0
6. मछली एवं उससे निर्मित वस्तुए	2.0	1.6	2.2
7. अनाज ओर उससे निर्मित वस्तुएं	0.5	0.6	2.2
8. मॉस ओर उससे निर्मित वस्तुएं	0.4	0.2	0.9
9. सब्जियॉ और फल	1.1	0.8	1.3
10. कॉफी और उसके अनुकल्प	2.1	1.7	2.4
11. पशुओं के चारे की सामग्री	1.6	2.2	3.8
12. अनिर्मित तम्बाकु ओर चूरा	4.4	2.1	0.0

स्त्रोतः–आर्थिक समीक्षा 2008–09 सारणी–7,5 पृष्ठ A–101 से 103 से संकलित ।

सारणी– 4 से स्पष्ट है कि विश्व में चाय और मेट के निर्यात में वर्ष 1980 में भारत का हिस्सा एक चौथाई से अधि ाक (27.7 पतिशत) था जो निरन्तर घटकर वर्ष 2006 में 9.1 प्रतिशत रह गया । इसी प्रकार मसाले ,तम्बाकु ओर तम्बाकू और उत्पाद , काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं, अनिर्मित तम्बाकु और चूरा के निर्यात में भी भारत की हिस्सेदारी निरन्तर घटी है ।

विश्वव्यापी कृषि निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक चावल में बढी है तथा यह वर्ष 1980 में 3.7 प्रतिशत के बढकर 2006 में 14.0 प्रतिशत हो गई है ।

इसके अतिरिक्त अनाज और उससे निर्मित वस्तुएं, मछली एवं उससे निर्मित वस्तुएं, मछली एवं उससे निर्मित वस्तुएं, मॉस और उससे निर्मित वस्तुएं, सब्जियॉ और फल, काफी ओर उसके अनुकल्प पशुओं के चारे की सामग्री के निर्यात में विश्व में भारत की भागीदारी बढी है ।

निष्कर्ष

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। नियोजित आर्थिक विकास एवं हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है । किन्तु कुल निर्यात व्यापार में कृषि निर्यातों का प्रतिशत निरन्तर कम हो रहा है । कुल निर्यातों में कृषि का भाग 1960–60 में 44.2 प्रतिशत था जो घटकर 1990–91 में 19.4 प्रतिशत तथा 2007–08 में 11. 6 प्रतिशत रह गया है। 2. देश में वर्ष 1991 से अपनाये गये व्यापार सुधारों का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों को बढावा देना है । इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के निर्यातों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है । विगत कई वर्षो से अपनायी गई नवीन व्यापार नीतियों के फलस्वरूप निर्यात के क्षेत्र में संरक्षणात्मक उपायों को हटाने की अनुकुल प्रतिक्रिया हुई है । 3. आर्थिक सुधारों के बाद विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा बढा है और यह वर्ष 2001 में 0.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2008 में 1.1 प्रतिशत हो गया है । किन्तु कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादों का भाग निरन्तर कम हुआ है जबकि अयस्क और खनिज, विनिर्मित वस्तुएं, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा बढ़ गया है। 4. विश्व व्यापी कृषि निर्यातों में भारत का हिस्सा निरन्तर घटा है । उदारीकरण के पूर्व विश्व के चाय निर्यात में भारत का भाग लगभग एक चौथाई था जो कि उदारीकरण के बाद निरन्तर घटकर वर्ष 2007–08 में केवल 9. 1 प्रतिशत रह गया है । विश्व कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी सबसे अधिक चावल में बढी है तथा यह 1980 में 3. 7 प्रतिशत बढकर 2006 में 14.0 प्रतिशत हो गई है। 5. भारत के कृषि निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि नही होने के लिये देश की द्रीव गति से बढ रही जनसंख्या प्रमुख रूप से उत्तरदायी है । इसके साथ ही विकसित देशों की विभेदात्मक प्रशुल्क नीतियॉ, विदेशी ऋणों का बढता भार, श्रेष्ठ किस्म के उत्पादों की कमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव भी प्रमुख चुनौतियॉ बनकर उभरे है । इसके अतिरिक्त भारत को विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक ओर जहॉ विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है , वहीं दूसरी ओर चीन, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, श्रीलंका आदि विकासशील देशों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है ।

सुझाव

1. भारत में कृषि उत्पादता का स्तर अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है । अतः कृषि में निर्यात योग्य अतिरेक बढाने के लिये कृषि उत्पादों की उत्पादकता में और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है । इसके लिये सभी कृषि आगतों, यथा– उत्तम बीज, खाद, कीटनाशक दवाएॅ, ऋण, विद्युत , सिचाई सुविधाओं की उपलब्धता बढानी होगी । कृषि को जीवन–यापन का साधन के स्थान पर एक लाभदायक व्यवसाय बनाना होगा। 2. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं भारत द्वारा उदारीकरण की नीति को अपनाने के बाद कृषि निर्यात व्यापार को बढाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है । अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि कार्यकुशलता में सुधार करके उत्पादन लागत को कम करने तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में श्रेष्ठता लाने के प्रयास किये जाये इसके लिये शिक्षित युवाओं को कृषि व्यवसाय को अपनाने के लिये प्रेरित करना आवश्यक है । 3. देश में निर्यात संबंधी सूचनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार तथा निर्यात व्यापार के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) का अधिक प्रयास किया जाना चाहिये । भारतीय कृषि उत्पादों का विदेशों में प्रचार कम है क्योकिं इस दिशा में किये गये सरकारी प्रयास अधिक प्रभावी नही रहे है, इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । सूचना – प्रौद्योगिकी एवं संचार सुविधाओं का विस्तार करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा । 4. कृषि निर्यातों मे वृद्धि के लिये बाजार का विस्तार करना आवश्यक है । संरक्षणात्मक प्रतिबंध लगाने वाले विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करके भारतीय निर्यातों का बाजार विस्तृत किया जा सकता है । अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों का भाग भारत के विदेशी व्यापार में बहुत कम है ये भारतीय कृषि निर्यात के लिये में बडी मण्डियां बन सकते है । इन देशों के साथ–साथ मध्यपूर्व एशिया के विकासशील देशों में भी भारत के निर्यात बढने की पर्याप्त सम्भावनाएॅ है । इन सुझावों को कार्य रूप में परिणित करने पर भारत के निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Jalan, Bimal, the Indian Economy, Problems and Prospects, New Dehli, 1992 . 2. Jhingan, M.L. Economics of Development ant planning, Vrinda Publicarions (P) Ltd. Dehli, 2007, Page 382 . 3. Singh, S.p. , Economics Development and planning,s chand and company Ltd. New Dehli, 2003, page 302-03. 4. Dutt, Ruolra & Sundaram, K.p.m, Indian Economy, s chand and company Ltd. New Dehli, 2009, page 636-37 . 5. Jalan, Bimal, India's Economic policy : preparing for the Twenty First century, New Dehli, 1996, page 102. 6. मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिसिंग हाऊस, मुम्बई, 2006 पृष्ठ 578 7. विदेश व्यापार नीति 2004–2009, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 2005, पृष्ठ– 39 8. आर्थिक समीक्षा 2008–09, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक प्रभाग, नई दिल्ली, 2009 , पृष्ठ– 142